

नाके पर रुकने की जरूरत भी नहीं होगी। उस Fast Track Card में blood group, driving licence, गाड़ी की पूरी डिटेल्स से लेकर सब प्रकार का डेटा रहेगा, ऐसा प्रोविजन किया गया है। नया कानून आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का पूरा उपयोग करके सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो आपने कहा, वह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या कस्टमर्स का डेटा फीडबैक लाने का कोई सिस्टम आएगा?

श्री नितिन जयराम गडकरी: सर, अभी 1993 का जो प्रेजेंट ऐक्ट है, जिसके बारे में मैंने अभी सम्मानित सदस्य महोदया के जवाब में भी कहा, एक बात तो यह है कि वह Concurrent List में है, दूसरी बात है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग कानून लगाती है, जिससे केन्द्र सरकार के पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं। दोनों को एक सहमति पर लाते हुए हमें बहुत कठिनाई महसूस हुई, क्योंकि अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग मत हैं। उनको लगा कि हम उनके अधिकार छीन रहे हैं, लेकिन अब दोनों मिलकर एक फ्रंट पर आ गए हैं। इसके लिए मैं इसी सदन में ऐक्ट लाऊंगा और जब आपके सुझाव लेकर वह मंजूर हो जाएगा, तो आप जो कह रहे हैं, वे सब अपेक्षाएं उस नये ऐक्ट में पूरी हो जाएंगी। वर्ल्ड में इस क्षेत्र में जो सबसे standardized countries हैं, USA से लेकर UK तक, हम उनके संपर्क में हैं। लंदन के पास स्वेल् में एक इंस्टीट्यूट है, जहां यह रिकॉर्डिंग होती रहती है कि हर चौक पर किस समय कौन सी गाड़ी जा रही है। मैं अभी यह इंस्टीट्यूट देखने के लिए गया था। आगे चलकर हमने intelligent traffic system का पूरी तरह से प्रोविजन कर लिया है जब यह intelligent traffic system आएगा, तो मंत्री जी हों या कोई अन्य हो, जो थोड़ा भी ऐक्ट का वॉयलेशन करेगा, 24 घंटे के अंदर उसके घर में टिकट चला जाएगा। इस सिस्टम में पुलिस की जरूरत ही नहीं होगी। प्रेजेंट सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करने की बात प्रेजेंट ऐक्ट में नहीं है, इसलिए आपका सहयोग लेकर जब हम नया ऐक्ट पास करेंगे, तो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट भी करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।

Investment in highways and ports

*80. SHRI RIPUN BORA: Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Government proposes to accumulate ₹ 25 lakh crore out of budgetary support for investment in highways and ports;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) the foreign funds contracts between the stakeholders therefor; and
- (d) the details of projects where these funds would be utilized and the investment process therein?

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) No Sir. The Government has allocated a total Gross Budgetary Support (GBS) of ₹ 46,834 crores including cess and toll remittance for 2016-17 for the Ministry of Road Transport & Highways. In addition, Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) of ₹ 59,279 crores has also been allowed to be raised for Highways in 2016 -17. For Ministry of Shipping, the Government has allocated a total GBS of ₹ 1531 crores. In addition, IEBR of ₹ 3183.14 crores has also been allowed.

There is a proposal to spend around ₹ 7 lakh crores to develop National Highways of around 50,000 kms. in the next 5 years. For Sagarmala port development the project cost is ₹ 73,375 crores and in respect of Sagarmala Port modernization it is ₹ 9891 crores.

SHRI RIPUN BORA: Mr. Chairman, Sir, I am putting this question on the basis of a very tall claim made by the hon. Minister in 'The Hindu' dated 20.1.2016, wherein the Minister said that he was going to raise ₹ 25 lakh crores as foreign investment for improvement of National Highways, Ports .. and Shipping. But in the reply, the hon. Minister has totally denied this. I have no issue on this. At the end of the reply, the Minister has mentioned that ₹ 7 lakh crores are going to be spent by his Ministry for development of national highways covering around 50,000 kilometres. My question is that in these 50,000 kilometres, whether the maintenance of the national highways is included or this is exclusively for new construction. This is my question.

श्री नितिन जयराम गडकरी: माननीय सभापति महोदय, हमारे डिपार्टमेंट में चार प्रकार से काम करने की पद्धति है। पहला, जो बजट में हमको पैसा मिलता है, उसको हम ईपीसी कहते हैं, जैसे आज टोल और सेस इत्यादि सब मिलाकर हमारा जो बजट आता है, उसमें करीब 65 या 66,000 करोड़ रुपये गवर्नमेंट के हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, जो 100% पब्लिक-प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से होते हैं, जिनको बीओटी प्रोजेक्ट कहा जाता है। वे प्रोजेक्ट अलग हैं। हमने तीसरा जो एक नया चालू किया है, उसका नाम "एन्यूटी हाइब्रिड" है, जिसमें हम लैंड एक्विजिशन करेंगे, एनवायरनमेंट क्लीयरेंस करेंगे। फिर 80 परसेंट लैंड एक्वायर करने के बाद प्रोजेक्ट एलॉट करेंगे और प्रोजेक्ट में 40 परसेंट गवर्नमेंट की तरफ से देंगे, क्योंकि बीच में इस सेक्टर की हालत ठीक नहीं थी। टोल सरकार इकट्ठा करेगी और टोल इकट्ठा करने के बाद बैंक इंटरेस्ट प्लस तीन परसेंट प्रॉफिट लेकर एन्यूटी बेसिस पर उसे रिटर्न करेगी। जब हमारी सरकार आई तब इस रोड सेक्टर में करीब 403 टोल प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें एमाउंट 3 लाख 85 हजार करोड़ रुपए का था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी केवल 10-11 प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें कलेक्शन 25 से 30 हजार करोड़ रही। काफी कॉम्प्लीकेशंस थे, काफी प्रोजेक्ट्स क्लीयर हो गए हैं।

सर, दूसरी बात यह है कि केवल रोड मिनिस्ट्री ने मार्च एंड तक 2 लाख 10 हजार करोड़ रुपए के कांटेक्ट्स एलॉट किए हैं। लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, वह यह होती है कि आप लाखों करोड़ में बात कर रहे हैं और बजट तो 22 हजार करोड़ रुपए का है, यह पैसा कहां से आ रहा है? यहां महाराष्ट्र के जितने सदस्य होंगे, उन्हें पता होगा कि जब मैं वहां मंत्री था, तो 1996-97 में सरकार से 10 करोड़ रुपए लिए थे और 4000 करोड़ पब्लिक से इकट्ठे किए थे और 8000 करोड़ के काम किए थे और वे पैसे वापस हो गए हैं। जब मैं यह 25 लाख करोड़ रुपए की बात करता हूं, तो इसमें दो प्रकार की बातें आती हैं। इसमें 12 लाख करोड़ रुपए में चारों हेड्रोज में जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, वे प्रोजेक्ट्स हैं। रोड्स एंड अमेनिटीज के 1300 स्पोर्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें 70 का टेंडर निकला हुआ है। रोड सेक्टर में हम लोग 36 लॉजिस्टिक पार्क्स रिंग रोड पर बना रहे हैं। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख करोड़ तक है। सरकार के पैसों से तो इसमें तीन-चार लाख करोड़ ही होगा, यह पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हाइब्रिड एन्यूइटी के साथ हो रहा है। जब शिपिंग की बात हुई, तो यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह इंटरनेशनल कंसलटेन्सी जो मैकेजी और बाकी हैं, उन्होंने रिपोर्ट में दिया है। केवल सागर माला प्रोजेक्ट में 12 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई है, ऐसी उन्होंने लिखित रिपोर्ट दी है।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री नितिन जयराम गडकरी: सर, थोड़ा दो मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं। 12 लाख करोड़ रुपए में से 4 लाख करोड़ रुपए वह पोर्ट रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट रेलवे कनेक्टिविटी मैकेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ पोर्ट्स, तो 4 लाख करोड़ रुपए उसके ऊपर है। उसी रिपोर्ट में 27 इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं, जो पोर्ट क्ले डेवलपमेंट आते हैं, उसमें करीब 12 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आने वाली है। इसके अलावा गंगा में 4000 करोड़ रुपए का लोन मंजूर हुआ, उसमें से 24000 करोड़ रुपए के काम इनलैंड वाटरवेज में एलॉट हो गए हैं। उस समय कहा था कि आपका टारगेट क्या है? मैंने मंत्री होने के नाते कहा था कि करीब 12 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है, यह हम लोग रोड सेक्टर में करेंगे और करीब 12 से 13 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम पोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, शिपिंग और इसमें करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री नितिन जयराम गडकरी: सर, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि यह हिंदुस्तान के इतिहास का पहला साल था, जिसमें हमारे 12 मेजर पोर्ट्स और तीन फ्लेगशिप ऑर्गेनाइजेशंस कोचीन शिपयार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और Dredging Corporation का प्रॉफिट करीब-करीब 6 करोड़ रुपए मिला है और all are in profits.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री नितिन जयराम गडकरी: सर, आखिर में उनका जवाब दे देता हूं कि यह जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कह रहे हैं, यह सभी के लिए अच्छा होगा कि यह जानकारी मिल नहीं पाएगी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में हम एक रोड बना रहे हैं, उसके लिए हमने बैंक से 3000 करोड़ रुपए

बैंक से 12 परसेंट के हिसाब से लोन लिया था। मैंने उनसे कहा कि आप डॉलर में टर्न-ओवर करते हो, रुपए में क्यों लेते हो? हमने यह कहा कि हम रुपया फोरेक्स में लोन लेंगे, तो 2600 करोड़ रुपए का लोन हमें 2.92 यानी तीन परसेंट से कम रेट में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में डॉलर में मिला है।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री नितिन जयराम गडकरी: हमारे लोन का डॉलर में करने में 50 हजार करोड़ की कैपेसिटी है। यह मैंने सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को मिलाकर बात कही है।

MR. CHAIRMAN: Second question; quickly, please.

SHRI RIPUN BORA: Sir, I want to know from the hon. Minister whether the Minister will institute a departmental inquiry into the very, very bad quality of work in the North Bank of Assam, to which I belong. The four-laning work on the road from Biswanath Chariali to Itanagar of Arunachal Pradesh, which is in front of my house, is going on there. Through RTI, I have collected the DPR on the plan estimate. But on the field, I have seen that the layer of the land and the layer of the metal is not as per the DPR and the Plan estimate. So, will the hon. Minister institute a departmental inquiry into these irregularities?

श्री नितिन जयराम गडकरी: सर, पहली बात तो यह है कि अब हम सीमेंट काँक्रीट के रोड बना रहे हैं। यह पुरानी सरकार के डीपीआर थे, अब मैंने मेंडेटरी सीमेंट काँक्रीट किया है और मैं दावा करूंगा कि 25 साल तक आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होगी।

श्री रिपुन बोरा: यह पुरानी सरकार का नहीं है, आपकी सरकार का है।

श्री नितिन जयराम गडकरी: आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**... सुन लीजिए। आप कभी मेरे पास नहीं आए। इस सदन के सब लोग आते हैं।

श्री रिपुन बोरा: हमने चिट्ठी लिखी है।

श्री नितिन जयराम गडकरी: मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आइए। आप वहां उस रोड की बात कीजिए, मैं अधिकारियों को बुलाता हूँ और अगर क्वालिटी ठीक नहीं होगी, तो कड़क कार्रवाई होगी। किसी को भी फेवर नहीं किया जाएगा। आप अपना पत्र दीजिए। हम इन्क्वायरी करेंगे और कार्रवाई करेंगे।

दूसरी बात, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि हमने असम और नॉर्थ-ईस्ट को मिलाकर 40,000 करोड़ के काम के वर्क ऑर्डर दे दिए हैं। आने वाले समय में नॉर्थ-ईस्ट के लिए एक लाख करोड़ के काम करने का हमारा लक्ष्य है। आप आइए, हम आपका काम जरूर करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. The House is adjourned till 2.00 p.m.
